

गोरखपुर के निवर्तमान सांसद योगी आदित्यनाथ जी के दूसरे कार्यकाल की कुछ अतिविशिष्ट उपलब्धियाँ एक नजर में

1. चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में :

- (i) बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर की मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के कारण मान्यता समाप्ति के आदेश को निरस्त कराकर उसे बहाल कराना।
- (ii) गोरखपुर जिला चिकित्सालय (जनरल एवं महिला) के जीर्णोद्धार के लिए उत्तर प्रदेश हेल्थ डेवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत 7.50 करोड़ रूपया स्वीकृत कराना।
- (iii) सम्बन्धित विधानसभाओं के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना।
- (iv) श्री गोरक्षनाथ मन्दिर परिसर में गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय की स्थापना जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा सम्बन्धी प्रायः सभी विभाग और उपकरण उपलब्ध है तथा रोगियों को अत्यन्त सस्ते दर पर परामर्श, उपचार और सेवा उपलब्ध होती है।

2. दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्र में :

- (i) दूरदर्शन केन्द्र गोरखपुर के लिए आवासीय व्यवस्था एवं पुराने उपकरणों की जगह नये उपकरण लगाने हेतु 5.60 करोड़ रूपये स्वीकृत कराना।
- (ii) आकाशवाणी केन्द्र गोरखपुर के लिए एफ. एम चैनल स्वीकृत कराना।

3. रेल सेवा के क्षेत्र में :

- (i) गोरखपुर से नई दिल्ली के लिए "गोरखधाम एक्सप्रेस" तथा "सप्तक्रान्ति एक्सप्रेस" गाड़ियों का संचालन।
- (ii) गोरखपुर से मुम्बई के लिए "गोदान एक्सप्रेस" का संचालन।
- (iii) गोरखपुर से दूर्ग तथा हरिद्वार के लिए गाड़ियों का संचालन।
- (iv) गोरखपुर रेलवे स्टेशन का माडल स्टेशन के रूप में विकास कराना।
- (v) गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उत्तर दिशा से भी प्रवेश द्वार तथा कम्प्यूटरीकृत टिकट कउण्टर की व्यवस्था कराना।
- (vi) गोरखपुर सिटी हाल्ट को पूर्ण स्टेशन के रूप में गोरखपुर सिटी स्टेशन के नाम से विकसित करना तथा नकहा स्टेशन का उच्चीकरण।
- (vii) गोरखपुर से सहजनवां तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण स्वीकृत कराना जिसमें डोमिनगढ़ से गोरखपुर के बीच कार्य प्रारम्भ।
- (viii) गोरखपुर से पिपराइच घुघली छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन।
- (ix) गोरखपुर-नौतनवा-गोण्डा लूप लाइन के आगमन परिवर्तन का कार्य प्रारम्भ कराना।
- (x) गोरखपुर-लखनऊ के बीच इण्टरसिटी ट्रेन का संचालन कराना।

4. सड़क यातायात एवं परिवहन के क्षेत्र में :

- (i) गोरखपुर महानगर में धर्मशाला बाजार में ओवरब्रिज स्वीकृत कराकर कार्य प्रारम्भ करवाना।
- (ii) राप्ती नदी पर बने वर्तमान राजघाट सेतु के बगल में नये सेतु के लिए 20 करोड़ रुपये स्वीकृत कराकर कार्य प्रारम्भ कराना।
- (iii) गोरखपुर महानगर में यातायात समस्या के समाधान तथा बाढ़ बचाव हेतु हावर्ट तथा माधवपुर बन्धों का उच्चीकरण कराकर इसे रिंग रोड के रूप में विकसित कराना।
- (iv) गोरखपुर के बाहरी भाग में चार लेन के एक बाई पास रोड तथा राप्ती नदी पर एक अन्य चार लेन के सेतु हेतु 400 करोड़ रुपये स्वीकृत कराना।
- (v) मानीराम तथा सजहनवां विधान सभा को जोड़ने के लिए गोवरहिया नाले तथा मानीराम व पिपराइच को जोड़ने के लिए चिलुआ नाले पर 1-1 करोड़ की लागत से पुलों का निर्माण कराना।
- (vi) नगर क्षेत्र में डोमिनगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ने के लिए रोहिन नदी पर एक पीपे के पुल का निर्माण कराना।
- (vii) कौड़िया ब्लाक में डोहरिया जगत बेला के बीच बढनी में तथा दहला घाट पर बाढ़ में बह गये पुलों की जगह नये पुलों का निर्माण करवाना।

5. वायु सेना के क्षेत्र में :

- (i) चौदह वर्षों से बन्द पड़ी वायु सेवा को पुनः शुरू कराकर गोरखपुर को लखनऊ, नई दिल्ली और कोलकाता से जोड़ना।
- (ii) गोरखपुर से काठमाण्डू (नेपाल) तक हवाई सेवा प्रारम्भ कराने के लिए अनवरत प्रयास तथा जुलाई 2004 से सेवा प्रारम्भ होने की आश्वासन।

6. विद्युत सेवा के क्षेत्र में :

- (i) ताला विद्युत परियोजना के अन्तर्गत भूटान से नई दिल्ली के लिए 1000 मेगा वाट की लाइन का 400 के.बी.ए. का एक सब स्टेशन गोरखपुर के लिए स्वीकृत कराकर 65 करोड़ रुपये अवमुक्त करवाना।
- (ii) संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विधान सभाओं के 100 गाँवों में विद्युतीकरण।

7. बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में :

- (i) प्रायः प्रतिवर्ष गोरखपुर महानगर एवं आस-पास के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ की विभीषिका से स्थायी बचाव हेतु 100 करोड़ रुपये की लागत से राप्ती बेसिन परियोजना स्वीकृत करवाना।
- (ii) महानगर को बाढ़ से बचाने के लिए हावर्ट तथा माधवपुर बांध का उच्चीकरण।

8. उद्योग के क्षेत्र में :

- (i) गोरखपुर को उत्तरी भारत का वस्त्र उद्योग सम्बंधी प्रमुख केन्द्र बनाने के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में पावरलूम सर्विस सेन्टर की स्थापना करवाना।
- (ii) गोरखपुर को टेक्सटाइल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 'टेक्सटाइल सेन्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट स्कीम' टी.सी.आई.डी.एम. के अन्तर्गत पावरलूम पार्क तथा हथकरघा विकास एवं डिजाइन केन्द्र के रूप में घोषित कवाना।

- (iii) गोरखपुर में पावरलूम इकाईयों को आधुनिक मशीनरी के लिए 50 लाख रुपये तक कर्ज लेने की सुविधा दिलाना और सीधी सब्सिडी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करवाना।
- (iv) पावरलूम कारीगरों के लिए नयी सामूहिक बीमा योजना लागू करवाना जिसके अन्तर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 80,000 रुपये तथा प्राकृतिक मृत्यु होने पर 50,000 रुपये बीमा प्राप्त होगा। इसमें सालाना प्रीमियम बड़ा हिस्सा केन्द्र सरकार तथा जीवन बीमा निगम की ओर से भरा जायेगा।
- (v) हथकरघा बनकर परिवारों के लिए आर्टीजन क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम्भ करवाना जिसके अन्तर्गत 1.25 करोड़ आर्टीजन तथा हथकरघा बुनकर परिवारों को 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध प्राप्त हो सकेगा।

9. शिक्षा के क्षेत्र में :

- (i) गोरखपुर में दो नये केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना।
- (ii) सहजनवां में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना।
- (iii) गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 38 कक्षाएँ, हॉल, पुस्तकालय वाचनालय का निर्माण तथा कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा।
- (iv) मूक बधिर एवं अन्ध विद्यालय में जीर्णोद्धार एवं विकास।

10. डाकघर एवं दूरभाष सुविधा के क्षेत्र में :

- (i) संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में 10 नये डाकघरों की स्थापना।
- (ii) संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में 15 नये दूरभाष एक्सचेंजों की स्थापना तथा 5 एक्सचेंजों का उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण।

11. जन सुविधाओं के विकास के क्षेत्र में :

- (i) गोरखपुर बस स्टेशन तथा गोरखपुर जंक्शन, रेलवे स्टेशन एवं अन्य अनेक सार्वजनिक स्थानों पर पथिक निवासी का निर्माण।
- (ii) चन्द्रलोक कुष्ठाश्रम, राजेन्द्र नगर कुष्ठाश्रम तथा गोरखपुर सेन्ट्रल जेल में चहार दीवारी प्रतीक्षा कक्ष और जन सुविधाओं का विकास।
- (iii) गोरखपुर महानगर में कलेक्ट्री बार एसोसिएशन, कमिश्नरी बार एसोसिएशन, सिविल बार एसोसिएशन, विश्वकर्मा मन्दिर (जटाशंकर) में पुस्तकालय, वाचनालय तथा शेड आदि का निर्माण।
- (iv) संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में डोहरिया शहीद स्मारक स्थल (पाली विकास खण्ड) और सहजनवां तहसील के समीप वाचनालय तथा पुस्तकालय, झुंगिया तथा जंगल बहादुर अली शेखपुरवा (चरगावां विकास खण्ड) में व्यायामशाला, साखी तथा हिरुआ (जंगल कौड़िया वि.ख.) गाँव में यात्री विश्रामगृह, बास स्थान (भटहट वि.ख.) में धर्मशाला, ग्राम सभा सरहरी (जंगल कौड़िया वि.ख.) में तथा ग्राम प्रानपुर (सहजनवां वि.ख.) में यात्री विश्रामगृहों का निर्माण।
- (v) संसदीय क्षेत्रान्तर्गत गोरखपुर महानगर में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तथा महेबा चुंगी मेडिकल कालेज गेट, सहजनवां तहसील के समीप झुंगिया चरगावां सहित अनेक स्थानों पर सुलभ शौचालयों का निर्माण।

गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की चिरलम्बित कुछ प्रमुख समस्याएँ इनके समाधान की दिशा में सांसद योगी आदित्यनाथ की भूमिका

लोक जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन समस्याओं का अन्त नहीं है और इस बात में भी सन्देह नहीं है कि इन समस्याओं से जूझ कर इन्हें समाधान तक पहुँचाने से जहां व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता का मूल्यांकन होता है वहीं वर्तमान एवं भविष्य के विकास का रास्ता भी खुलता है। इसलिये कृतित्ववान व्यक्ति समस्याओं से आँख चुराने या पलायन करने के बजाय उनको चुनौती के रूप में स्वीकार कर समाधान के लिये प्रयत्नशील रहता है। व्यक्तिगत समस्याओं से लोग खुद भी यथाशक्ति जूझते हैं किन्तु एक जन-प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं से चाहे वे सार्वजनिक हों, चाहे मतदाताओं की व्यक्तिगत समस्याएं हो बराबर दो चार होना पड़ता है और लोग उससे अपेक्षा करते हैं कि वह प्रतिनिधि होने के नाते उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन से लेकर संसद से सड़क तक सुलझावे। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के निवर्तमान सांसद योगी आदित्यनाथ जी ने जब दूसरी बार 1999 में हुए संसदीय चुनाव में पुनः विजयश्री प्राप्त कर भारतीय संसद में प्रवेश किया तब इस संसदीय क्षेत्र की कई चिरलम्बित समस्याओं के समाधान की नैतिक और प्रतिनिधि होने के कारण कर्तव्यपरक जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गयी। उनके प्रमाणित पराक्रम और कृतित्व से लोगों की अपेक्षाएं जगीं और उनसे अपेक्षा की जाने लगी कि वे क्षेत्र की कुछ चिरलम्बित प्रमुख समस्याओं का अपने दूसरे कार्यकाल में प्राथमिकता के साथ समाधान करेंगे। क्षेत्र की कुछ समस्याएं 1998 में जब योगी आदित्यनाथ जी प्रथम बार भारतीय संसद में सबसे कम उम्र के एक सांसद के रूप में चुने गये थे उसके पूर्व से लम्बित थी और बारहवीं लोकसभा के 13 महीनों के अति संक्षिप्त कार्यकाल में योगी जी की पहल के बावजूद इनका सम्पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो पाया था। दूसरी बार प्रतिनिधि चुने जाने पर उन्होंने पुनः बिना समय गवाये उन सभी समस्याओं के यथा सम्भव समाधान का बीड़ा उठा लिया और ईमानदारी तथा गम्भीरता से जनता सहित शासन प्रशासन का बीड़ा उठा लिया और ईमानदारी तथा गम्भीरता से जनता सहित शासन प्रशासन के सहयोग से काफी हद तक अपने प्रयत्नों में उल्लेखनीय सफलता भी प्राप्त की। कम उम्र से ही सांसद के रूप में चुने जाने पर लोगों को लगता था कि योगी आदित्यनाथ जी के मार्ग में अनुभव की कमी स्वाभाविक रूप से आड़े आवेगी किन्तु क्योंकि यशस्वी और तेजस्वी पुरुष अपने कृतित्व और पुरुषार्थ के लिये उम्र के मोहताज नहीं होते इसलिये योगी आदित्यनाथ जी ने भी थोड़े समय में अपनी स्वयं स्फूर्त सेवाभावना पर दुःख कातरता, कर्मठता तथा सूझ-बूझ के बल पर सभी आशंकाओं को निर्मूल करते हुए संसद और क्षेत्र में भी अपने कर्तृत्व की ऐसी धाक जमा दी जिससे न केवल गोरखपुर की तमाम लम्बित समस्याओं का समाधान आसान हो गया बल्कि हर आम व खास व्यक्ति को यह भली-भाँति एहसास हो गया कि उसे योगी आदित्यनाथ जी के रूप में एक चिर-प्रतीक्षित अनमोल रत्न मिल गया है जो हर आंधी तूफान में, विकट से विकट परिस्थितियों में अपने सुख-दुःख व आराम की चिन्ता किये बिना उनके साथ खड़ा हुआ है। यद्यपि समाचार पत्रों के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी के भगीरथ प्रयत्नों द्वारा गोरखपुर क्षेत्र की तमाम चिरलम्बित समस्याओं के समाधान की थोड़ी बहुत जानकारी सबको अवश्य हुई होगी तथापि वर्षों से जन-मानस को मथ रही समस्याओं के समाधान में निवर्तमान सांसद की भूमिका और उपलब्धियों का प्रमाणित तथ्यपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना, आम लोगों को इसकी पूरी जानकारी देना, अत्यन्त आवश्यक है ताकि जनता और मतदाता अपने प्रतिनिधि के कृतित्व को, उसकी उपलब्धियों को न केवल सही रूप में जाने-पहचाने बल्कि विरोधियों के दुष्प्रचार का भी पर्दाफाश हो सके। इसी प्रयोजन से संक्षेप में गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की कुछ चिरलम्बित समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनके समाधान के लिये यहाँ के निवर्तमान सांसद योगी आदित्यनाथ जी के प्रयत्नों से मिले परिणामों का यथा सम्भव विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है :

गीडा के विकास की समस्या :

नोएडा की तर्ज पर गोरखपुर को भी औद्योगिक विकास की उपलब्धियों से विकसित करने के उद्देश्य से गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत सहजनवां विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए 1990 में औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की स्थापना की गयी। इसके लिये शासन के निर्देश पर प्रशासन में नेवास, झुगियां, बड़गहन, कालेसर एवं जुड़ियान गाँवों में स्थित किसानों की 172.68 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया था। स्थापना काल के समय से ही किसानों को उनकी अधिग्रहीत भूमि का उचित मुआवजा न मिलने के कारण जन-आन्दोलनों की वजह से गीडा का अपेक्षित विकास बाधित रहा। सांसद के रूप में अपने 13 महीनों के प्रथम कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी ने सफलता पूर्वक प्रशासन और किसानों के बीच समझौता कराकर मुआवजा सम्बन्धी चिरलम्बित विवाद का समाधान कराया था और तब यहाँ योजनानुसार औद्योगिक इकाईयों के लगाने का मार्ग प्रशस्त हो चुका था। इस दिशा में क्षेत्रीय सांसद योगी आदित्यनाथ जी और कुछ करते इसके पूर्व ही 13 महीनों में 12वीं लोकसभा भंग हो गयी और फिर कुछ समय के लिये औद्योगिक इकाईयों का गीडा में स्थापित होना अवरूद्ध हो गया। सांसद के रूप में योगी जी के दूसरे कार्यकाल में पुनः गीडा क्षेत्र के विकास की समस्या सामने आयी जिसके समाधान के बिना नोएडा की तर्ज पर गोरखपुर के औद्योगिक विकास का सपना साकार नहीं हो सकता था। इसलिये योगी जी ने जन-प्रतिनिधि होने के नाते इस ओर प्राथमिकता के साथ ध्यान दिया। इसलिये चूंकि बुनियादी सुविधाओं और पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में उद्योगपति इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयाँ लगाने को तैयार नहीं थे इसलिये पहली आवश्यकता यह थी कि उन्हें आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का स्पष्ट आश्वासन दिया जाय और वहाँ के वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाया जाय। ऐसी स्थिति में योगी जी ने जहाँ एक ओर प्रयास कर गोरखपुर के उद्योगकर्मियों को वांछित भरोसा दिया वहीं दूसरी ओर शासन और प्रशासन से बराबर सम्पर्क व संपर्ष कर गीडा के औद्योगिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। योगी जी के प्रयत्नों से उत्तरी भारत में वस्तु उद्योग के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में गोरखपुर को विकसित करने के लिये केन्द्र सरकार के सहयोग से 44 लाख की लागत से एक "पावरलूम सर्विस सेन्टर" की स्थापना हुई तथा गोरखपुर का टेक्सटाईल्स सिटी के रूप में विकसित करने के लिये "टेक्सटाईल सेन्टर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट स्कीम" के अन्तर्गत इसे पावरलूम पार्क तथा हथकरघा विकास और डिजाईन केन्द्र के रूप में केन्द्रीय वस्त्र मंत्री श्री सैयद शाहनवाज हुसैन से घोषित कराया। तदनुसार गीडा में 80 एकड़ भूमि में 18 करोड़ की लागत से टेक्सटाईल उद्योग के विकास हेतु स्थापना विकसित करने के लिये "नार्दन इण्डिया टेक्सटाईल एसोशियेशन" ने एक योजना तैयार की है जिससे यहाँ पर 300 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश होगा तथा हजारों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा इससे उत्साहित होकर गोरखपुर के कई उद्योगपतियों ने अपनी कई छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाईयाँ गीडा में स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है जिससे वहाँ उत्तरोत्तर विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हमें विश्वास है कि योगी जी के प्रयत्नों से गोरखपुर को नोएडा की तर्ज पर विकसित करने का सपना शीघ्र ही पूरा हो जायेगा।

धर्मशाला बाजार (गोरखपुर महानगर) रेलवे पुल के ऊपर ओवरब्रिज बनाने की समस्या :

गोरखपुर महानगर के धर्मशाला बाजार में मेडिकल कालेज रोड पर सड़क के ऊपर रेलवे का एक छोटा सा डाट का पुल है। पुल की निचाई के कारण उसके नीचे की जमीन भी दोनों तरफ की सड़कों से नीची है जिसके कारण आये दिन यहाँ अक्सर तीन से चार फुट पानी लग जाता है जिससे घंटों यातायात बाधित हो जाता है और यात्रियों व नागरिकों को आने-जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि मुख्य नगर को रेलवे लाईन के उस पार बसे भाग से जिसमें राष्टीनगर कालोनी के सभी फेज, मेडिकल कालेज, चरगावा, दूरदर्शन केन्द्र, पादरी बाजार, फातिमा अस्पताल, गीता

वाटिका व पिपराईच आदि कई महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित हैं - जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग है जिस पर जल-जमाव के कारण अक्सर जाम लग जाता है और लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। यह महानगर में यातायात की एक बड़ी समस्या है जो वर्षों से नागरिकों की जर्बदस्त चिन्ता का कारण बनी रहा है किन्तु आश्वासनों के बावजूद महानगर की इस चिरलम्बित यातायात समस्या का समाधान करने के लिये योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल से पूर्व कोई सार्थक पहल नहीं हो पायी थी। मार्च 1998 में योगी आदित्यनाथ जी पहली बार गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय संसद के लिये चुने गये तब जन-प्रतिनिधि होने के कारण यह विकट समस्या उनके सामने भी आयी और उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार इसे पूरी गम्भीरता से राज्य व केन्द्र सरकार के समक्ष उठाया। बात अभी प्रारम्भिक सफलताओं के बावजूद पूरी तरह परवान नहीं चढ़ी थी कि 12वीं लोक सभा तेरह महीनों में भंग हो गयी। पुनः 13वीं लोक सभा में निर्वाचित होने पर सांसद के रूप में अपने दूसरी कार्यकाल में उन्होंने फिर इस समस्या को गम्भीरता से उठाया और 18 अक्टूबर 2001 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री राजनाथ-सिंह जी ने धर्मशाला ओवरब्रिज का नया शिलान्यास किया और तद्नन्तर शीघ्र ही ऊपरसेतु का निर्माण शुरू हो गया। शिलान्यास के बाद भी ओवरब्रिज के लिये समय-समय आवश्यक धन अवमुक्त कराने के लिये भी योगी आदित्यनाथ जी को लखनऊ और दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ी किन्तु इनका अदम्य उत्साह अन्तः सफल हुआ और शनैः शनैः आवश्यक धन की अपेक्षा पूर्ण होने पर क्रमशः काम बढ़ता हुआ अब अन्तिम चरण में है। इस प्रकार धर्मशाला पर ओवरब्रिज बनवाने की समस्या जिससे महानगर की जनता विगत कई दशकों से परेशान हो रही थी सांसद के रूप में योगी जी के दूसरे कार्यकाल की उल्लेखनीय उपलब्धि बनकर हमारे सामने प्रस्तुत है।

बाबा राघव दास मेडिकल कालेज की मान्यता समाप्ति की समस्या :

वर्ष 1998 में इण्डियन मेडिकल कौंसिल ने बाबा राघव दास मेडिकल कालेज गोरखपुर की एम०बी०बी०एस० उपाधि की मान्यता को समाप्त करने की सिफारिश सरकार से की क्योंकि कौंसिल द्वारा उक्त डिग्री के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार बाबा राघव दास मेडिकल कालेज में -

1. शिक्षकों के अधिकांश पद रिक्त हैं।
2. विभिन्न विभागों में लिपिक, टाइपिस्ट और स्टेनों के भी बहुत से पद रिक्त हैं।
3. नर्सों की संख्या भी मानक से काफी कम है।
4. छात्रावासों की संख्या और स्थिति मानक के अनुरूप नहीं है।

ज्ञातव्य है कि मेडिकल कालेज की उपर्युक्त कमियों की ओर मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया ने कई बार सर्व सम्बन्धित का ध्यान आकृष्ट किया था किन्तु उत्तरदायी लोगों ने कभी कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जिसके कारण आई०एम०सी० को विवश होकर उक्त कठोर सिफारिश करनी पड़ी। मान्यता समाप्ति की उक्त सिफारिश से बी०आर०डी० मेडिकल कालेज की एम०बी०बी०एस० डिग्री की मान्यता खतरे में पड़ गयी और यहां उक्त डिग्री के लिये अध्ययनरत छात्रों/छात्राओं के साथ मेडिकल कालेज का भविष्य भी अन्धकारमय हो गया। गोरखपुर से उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में अनेक कैबिनेट और राज्यमंत्री थे, विधायकगण भी थे किन्तु जब एक दो अपवादों को छोड़कर किसी से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला तब सभी प्रभावित लोग हार-थक कर सांसद योगी आदित्यनाथ जी के पास आये इन्होंने संकट की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल व्यक्तिगत रुचि लेकर इण्डियन मेडिकल कौंसिल और राज्य तथा केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया। योगी जी ने सर्व सम्बन्धित को पत्र लिखकर एवं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी समझाया कि मेडिकल कालेज की कमियों के लिये वहां के अधिकारी

